प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुमाग-2

देहरादून : दिनांक / 0 अक्टूबर, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2016—17 में नगर पंचायत, पुरोला को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि नगर पंचायत, पुरोला द्वारा अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनसाश की स्वीकृति हेतु नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रस्ताव / आगणन उपलब्ध कराये गये हैं। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, पुरोला द्वारा निकाय क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार कुल ₹9.28 लाख (रूपये नौ लाख छब्बीस हजार मात्र) की धनराश की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराश को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेत् श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराश र लाख में)

घनराशि	स्वीकृत धन		to the Shirt State of Cal	क्र.सं.
.11	3.11	जाले नामे तोक में आवासीय भवनों का सुरक्षात्मक कार्य।	वार्ड	1-
.95	2.95	अस्पताल छाड़ा खड्ड के पास दीवार एवं सी०सी०व कार्य।	वार्ड	2-
# C	3.20	ad from kumola raod to Gandhi nagar. WN 05	Prot	4
*	3. 9.	ad from kumola raod to Gandhi nagar. WN 05 योग—	Prot	3-

2- उपरोक्त धनराशि निम्नलिखित शर्ती एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है :-

 उक्त धनराशि कुल ₹9.26 लाख (रूपये नौ लाख छब्बीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, पुरोला को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ग. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है अधवा उक्त हेतु पूर्व में घनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष घनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

III. कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अविध के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा

में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

ए. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुरितका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,
2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का

कड़ाई से पालन किया जाए।

VII. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं / कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

vIII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा

उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

 सभी निर्माण कार्य समय—समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

..2/-...

X. निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस०ओ०आर० के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

XI. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से

प्राप्त कर ली जाय।

жи. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

XIII. धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

XIV. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेंदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

XV. धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण

एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों; शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास—20 सहायक अनुदान/अंशर्वान/राज सहायता" के नामें डाला जाएगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxvII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—s./.6/.43.0/.48. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

(डी०एस० गर्ब्याल) सचिव।

1789 (1)/IV(2)-श0वि0-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखांकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखांकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निजी सचिव, मां० मुख्यमंत्री जी / शहरी विकास मंत्री जी।

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

विश्व कोषाधिकारी, देहरादून।

विता अधिकारी, साईबर ट्रेजेरी, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

8 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।

9. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पुरोला।

बंजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11. गार्ड बुक ।

आज्ञा-से, <u>() ( डी०एम०एस०</u> राणा ) उप सचिव।